एक राष्ट्र, एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति ने प्रस्तुत की रिपोर्ट

एक राष्ट्र, एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) ने गुरुवार (14 मार्च) सुबह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी। 21-खंड, 18,626 पेज की विस्तृत रिपोर्ट में 11 अध्याय और अनुबंध शामिल हैं।

एक साथ चुनाव का क्या मतलब है :–

एक साथ चुनाव, जिसे लोकप्रिय रूप से "एक राष्ट्र, एक चुनाव" कहा जाता है, का अर्थ है एक ही समय में लोकसभा, सभी राज्य विधान सभाओं और शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों (नगर पालिकाओं और पंचायतों) के चुनाव कराना।

आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गईं। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश-एक चुनाव की परंपरा टूट गई। वर्तमान में, ये सभी चुनाव प्रत्येक व्यक्तिगत निर्वाचित निकाय की शर्तों द्वारा निर्धारित समय-सीमा का पालन करते हुए एक-दूसरे से स्वतंत्र रूप से आयोजित किए जाते हैं।

कोविंद समिति में कौन-कौन से सदस्य :–

समिति के सदस्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, पूर्व महासचिव, लोकसभा सुभाष सी कश्यप, वकील हरीश साल्वे और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी, कानून और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल विशेष आमंत्रित सदस्य थे और डॉ. नितेन चंद्रा हाई लेवल पैनल के सचिव थे.

संविधान में संशोधन: दो चरणों में एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए।

पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव होंगे। इसके लिए संविधान संशोधन के लिए राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।
दूसरे चरण में, नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनावों को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के साथ इस तरह से समन्वयित किया जाएगा कि स्थानीय निकाय चुनाव लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के 100 दिनों के भीतर आयोजित किए जाएं। इसके लिए कम से कम आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी

एकल मतदाता सूची और चुनाव आईडी:

सरकार के सभी तीन स्तरों के चुनावों में उपयोग के लिए एकल मतदाता सूची और मतदाता फोटो पहचान पत्र तैयार करने के उद्देश्य से, संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए, ताकि भारत का चुनाव आयोग एक एकल मतदाता सूची और मतदाता फोटो पहचान पत्र तैयार कर सके। राज्य चुनाव आयोगों के परामर्श से मतदाता सूची और चुनाव आईडी। इन संशोधनों के लिए कम से कम आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी।

त्रिशंकु सदन आदि की स्थिति में:

त्रिशंकु सदन, अविश्वास प्रस्ताव या ऐसी किसी घटना की स्थिति में, सदन की शेष अवधि के लिए नई लोकसभा या राज्य विधानसभा के गठन के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जाने चाहिए।

लॉजिस्टिक आवश्यकताओं को पूरा करना:

समिति ने सिफारिश की है कि लॉजिस्टिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, भारत का चुनाव आयोग राज्य चुनाव आयोगों के परामर्श से पहले से योजना बनाएगा और अनुमान लगाएगा, और जनशक्ति, मतदान कर्मियों, सुरक्षा बलों, ईवीएम की तैनाती के लिए कदम उठाएगा। /वीवीपैट आदि, ताकि सरकार के तीनों स्तरों पर एक साथ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो सकें।

सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाए।